[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

is a Central Act. That is also why the Speaker's Secretariat has admitted the motion. Now because it is questioned by some Deputy Commissioner somewhere, does it mean that it becomes a State subject altogether ? It is the sovereign right of this House and the Central Government to enforce Central Acts throughout the territory of India. When this is questioned, the Speaker's Secretariat also has to come to our aid.

MR. SPEAKER : There is no point of order.

श्री बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि कुछ लीगल डिफीकल्टीज़ हैं ।

Here is our Constitution of India, art. 1 of which says :

> "The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule".

And in the First Schedule is included Jammu and Kashmir.

Every Indian citizen has certain fundamental rights.

MR. SPEAKER : We are not discussing all this now.

SHRI BALRAJ MADHOK : It is relevant. Article 370, to which referrence has been made, is a transitional provision. It has been there for the past 20 years. I want to know how long this sovereign Parliament is to be debarred from exercising any claim or authority over Jammu and Kashmir merely because of this transitory provision.

MR. SPEAKER : He can take steps to do what he thinks proper at a later stage. There is no point of order.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अब तक आप के इस आसन और पद की यह परम्परा रही है कि अगर सरकार का कोई मंत्री किसी प्रश्न का सही उत्तर न दे रहा हो, या तोड़-मारोड़ कर उत्तर दे रहा हो, तो आप उस को इस बात के लिए विवश करते हैं कि वह सही उत्तर दे कर सदन को, और देश को, संतुष्ट करे । जब राष्ट्रपति को जम्मू-काश्मीर की गवर्नमेंट को भंग करने का अधिकार है, जब वह जम्मू-काश्मीर में राष्ट्रपति-शासन स्थापित कर सकते हैं, तो क्या उन को यह अधिकार नहीं है कि वह जम्मू-काश्मीर में कोई जमीन खरीद सकें ? मेरा निवेदन है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करके इस प्रश्न का संतोष जनक उत्तर दिलायें ।

MR. SPEAKER : There is not point of order. He only wanted to ask a question. Shri S. S. Deshmukh started and got us into all this trouble.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH: You could give your opinion.

MR. SPEAKER : You have done very well ! Thank you.

12.25 hrs.

RE QUESTION ON PRIVILEGE

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 225 के तहत विशेषाधिकार के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ ।

MR. SPEAKER : The privilege motion has not yet been admitted. Only I would like to hear him.

श्री मधु लिमये : मैं संक्षेप में कुछ तथ्य आप के सामने रखना चाहता हूँ । उन को सुन कर आप इस बारे में फैसला कर सकते हैं ।

अप्रैल, 1967 में दिल्ली में पुलिस वालों का एक आन्दोलन चला था । उस सिलसिले में कई पुलिस वालों को सेवा से बरतरफ किया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए । आज भी वे मुकदमे चल रहे हैं । एक प्रश्न के जवाब में सरकार के द्वारा यह कहा गया कि इन मुकदमों पर इस वक्त चौदह, पंद्रह, हजार रुपया मासिक खर्च हो रहा है ।

पुराने सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन को अदालत में परिवर्तित कर के उस में ये मुकदमे चलाये जा रहे हैं। मैं स्वयं वहां गया था। वहां पर अदालत का कोई वातावरण नहीं है। वहां पर न स्टैन्ग-बेंडर है और न टाइपिस्ट हैं। चूंकि वहां पर पुलिस लाइन्स में से जाना पड़ता है इस लिए गवाह वहां पर नहीं जा सकते हैं। उन को सताया जाता है, धमकाया जाता है। ऐसी हालत में वहां पर ये मुकदमे चलाया जाना कानून और संविधान के बरखिलाफ़ है।

इस के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि ये मुकदमे दिल्ली के मैजिस्ट्रेट्स के सामने न चलें। इस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसले मेरे पास हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से पहला आर्डर यह दिया गया :

"As a statement has been made on behalf of the State that magistrates draw from States other than Delhi and Himachal Pradesh will be entrusted with the trial of these cases there is no need to pass any order because the applicants express themselves satisfied with this arrangement".

उस के बाद दूसरा आर्डर यह हुआ :

"It is agreed that the cases may be made over to the new magistrates proposed by the Attorney General. one from Rajasthan, one from Punjab and three from UP. Mr. S. K. Mehta has no objection if the cases are tried by them while sitting in Delhi. If there is any need for getting more magistrates to try the cases, they may in the same way be drawn from States other than Delhi and Himachal Pradesh. Let these cases be tranferred to the new magistrates".

सुप्रीम कोर्ट का अन्तिम आर्डर यह है :

"There is no objection to the trial of the cases by Shri Devendra Kumar. The State Government undertakes to replace Shri K. K. Kalia by another magistrate from any of the other three States, that is, Punjab, UP or Rajasthan who has not been on deputation from Delhi".

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार-बार कहने पर भी सरकार ने ऐसे मैजिस्ट्रेट बाहर से लाए हैं, जो डेपूटेशन पर थे, अर्थात् जो दिल्ली के ही थे। खैर, सुप्रीम कोर्ट की आज्ञाओं का सरकार जो उल्लंघन कर रही है, उस को मैं छोड़ देता हूं। लेकिन जिस अदालत में ये केस चल रहे हैं, उस में सरकार ने सशस्त्र पुलिस रखी हुई है। 22 मार्च, 1968 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4749 के भाग (सी) में पूछा गया था ;

"Whether any armed police is posted at the trial court" ?

उस का जवाब यह दिया गया :

"No, Sir".

इसलिए मैं स्वयं वहां गया। मैंने देखा कि वहां पर सशस्त्र पुलिस है।

एक जगह पर "फीमेल लाक-अप" लिखा हुआ था। मैं ने वकीलों और दूसरे लोगों से यह जानने की कोशिश की कि क्या वह सचमुच लाक-अप है। लोगों ने कहा कि यह पुराना पुलिस स्टेशन था; उस समय का लाक-अप है; अब बगल में ही नया बड़ा पुलिस स्टेशन बनाया गया है। मैं उस पुलिस स्टेशन पर गया। वहां के प्रमुख ने मुझे वह लाक-अप दिलाया, जो इस वक्त इस्तेमाल में है। जो सशस्त्र पुलिस वहां पर जगह जगह थी, मैं ने उन की तस्वीर खींचने की कोशिश की और एक फोटोग्राफर को कहा। मैं वहां पर पार्लियामेंटरी कार्य के लिए गया था। श्री यसवन्तराव चव्हाण ने जो जवाब दिया है, वह कितना असत्य है, यह साबित करने के लिए मैं सुबूत इकट्ठा करने के लिए गया था।

पुलिस कर्मचारी संघ के सैक्रेटरी को मैंने कहा था कि आप फिल्म और कैमरा लेकर आइये और मेरे साथ ये जो हथियार पुलिस वाले हैं इनकी तस्वीर खींच लीजिये। खेद की बात है कि मेरे चले आने के बाद उस फोटोग्राफर से फिल्म और कैमरा छीन लिया गया, उस की फिल्म को एक्सपोज किया गया, जिससे कि यह सारी फिल्म काली हो गई है। इतना

[श्री मधु लिमये]

ही नहीं, उस को डण्डे से मारा गया, पीटा गया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ फिल्में बचाने की कोशिश की। उस की दो तस्वीरें आई हैं, साफ नहीं हैं, लेकिन वहां हथियारी-पुलिस हैं, इतना साफ दिखाई देता है। आपकी इजाजत से मैं इसे आप के सामने रख रहा हूं।

अब उस फोटोग्राफर ने जो चिट्ठी पुलिस स्टेशन के अधिकारी को लिखी है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ.....

MR. SPEAKER : You need not read it.

श्री मधु लिमये : यह बहुत जरूरी है।

"To,

The Station House Officer,
Police Station, Civil Lines,
Delhi.

Jai Hind. As you are aware that on 26.4.68 I visited the courts at P.S. Civil Lines, and under the instruction of Shri Madhu Limaye, Member of Paliament, I took his photographs in front of the Trial Courts with armed guard posted there in front of the trial courts. As soon as I came out of the courts you alongwith Shri Ranjit Singh S.I. in uniform, H.C. Tirath Ram and S.I. Sant Singh in plain clothes caught hold of me and pushed me inside, beat me and tried to snatch the camera from my hands. When I resisted all of you abused me and pulled me by hair.. I told you that I could not hand over the camera to you as Shri Madhu Limaye, M.P., wanted me to get him the photographs; you all shouted at me and told me that you can set right anybody including Shri Madhu Limaye M.P...."

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात की जाती है.....

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : No.

श्री मधु लिमये : आप चुप बैठिये, प्रोफेसर साहब।

इस तरह की बातें, अध्यक्ष महोदय, हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं किसी व्यक्तिगत काम से वहां नहीं गया था, मैं केवल इस सदन की सेवा करने के लिये वहां गया था और आप जानते हैं मैं कभी भी बिना सबूत के नहीं बोलता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि कैमरा ले जा कर तस्वीर लेकर आयें और सदन के सामने प्रस्तुत करें। अगर मारने की धमकी मुझ को देते हैं, अध्यक्ष महोदय-वैसे तो कई बार मैं मार खा चुका हूँ, गृह मन्त्री चाहें तो और खिला सकते हैं, लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में उनकी निगरानी में ये जो सारे मामले हो रहे हैं और पुलिस के मुकदमों में जो धांधली हो रही है.....

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : Is it a point of order ?

MR. SPEAKER : It is motion on breach of privilege. I discussed it with the Home Minister. I want to hear facts before I decide on the question whether it is to be allowed as a motion for the breach of privilege. It is not a point of order at all.

श्री मधु लिमये : मैंने व्यवस्था का सुझाव दिया ही नहीं है, उस को एलाऊ न करने का क्या सवाल है। इन्होंने जो गलत जवाब दिया है, उस के बारे में दूसरी प्रक्रिया है। मैंने उन के विरुद्ध प्रिवलेज मोशन दिया ही नहीं है। जब भी गृह मंत्री उठते हैं तो ये उन की ताइद करने के लिये खड़े हो जाते हैं

SHRI SONAVANE : It is not a question of *thariff* here. I am asking the Speaker.

श्री मधु लिमये : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उन को पता ही नहीं है कि मामला क्या है। मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव स्टेशन हाउस आफिसर, जिसको दिल्ली में कहते हैं, अर्थात् इंस्पैक्टर इन्चार्ज, थानेदार, के खिलाफ है। अब इस में ब्रीच आफ प्रिवलेज कैसे आता है, इस के बारे में दो-तीन बातें.....,

MR. SPEAKER : Not now.

श्री मधु लिमये : ठीक है, मैं इतना ही कह रहा हूं। इस में लिखा है कि...

MR. SPEAKER : I have not yet admitted or decided whethecit is a breach of privilege or not. I only want to know the facts now. That is why I wanted to find out whether it is a breach of privilege or not. I shall decide after hearing the Home Minister. I wanted to know facts. Yesterday, you brought the matter to my notice and said that you wanted to move a privilege motion. Then I told the Home Minister that I should know the facts before I decide whether the motion should be admitted. I may not admit it later on, if I so decide. If I admit it, then we shall begin discussing.

श्री मधु लिमये : मैं एक ही वाक्य कहना चाहता हूं। "मे" में यह लिखा हुआ है कि

"To impede Member of Parliament in the performance of his duties..."

यह विशेषाधिकार का भंग है। तफसील में मैं अभी नहीं जाता हूं। इस लिये यह प्रिविलेज है।

SHRI M. R. MASANI (Rajkot) : Before you ask the Home Minister to reply—no doubt you will then decide whether there is breach of privilege or not—I want to say that the facts which the hon. Member has just now related are not of a very pleasant nature. They do show that when a Member of Parliament was engaged in what he considered to be his public duty, in finding out whether the statement made by the hon. Minister was or was not accurate, this was the attitude of the authorities. In certainly needs to be condemned. I think the Home Minister should look into it in view of the facts Mr. Limaye had brought to light and deal with that also.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I am glad you gave me an opportunity to explain the facts. Certainly a question was asked and the answer was given that there were no police guards in front of the courts, as he himself stated. I have not seen the place myself and I am speaking on the information that I have got. Certainly, if necessary I shall go and see the place myself.

I shall explain the whole position. The old police civil lines had been shifted to some new building which is in front of the police station. But at the same time these courts also have some persons in judicial custody, when cases are tried and sometimes people have to be sentenced. Sometimes people do not respond to summons. Therefore, if warrants are issued, they are to be kept in judicial custody. Therefore, some arrangements for armed guards is there. But there was no question of posting any armed guards as such for the courts. It is a basic fact.

Now what happened on the 28th ? As the hon. Member Madhu Limaye had stated ...(*Interruptions*) He himself admitted. If any officer threatened anybody to beat, etc. certainly it is bad. But what is the fact ? When hon. Member Madhu Limaye went there he was almost welcomed ; he was given whatever information he wanted ; as a matter of fact all possible courtesy was shown to Mr. Limaye. But Mr. Limaye wants to depend upon the statement made by some other person.

श्री मधु लिमये : यह सबूत है।

SHRI Y. B. CHAVAN : What is that evidence ? Merely showing some film is not evidence...(*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : उसकी फिल्म को छीन लिया, यह मेरा आरोप है। मेरे काम में बाधा डाली।

SHRI Y. B. CHAVAN : When I got this notice from the Parliamentary office. I asked the IGP to look into this matter. Now the IGP's report says that such an incident has not taken place. The letter to which he referred is written on the 27th and the incident seems to have taken place on the 26th. The person concerned says that he was not a professional photographer. He is a dismissed head constable who happened to be the secretary of the Karmachari Sangh. It is a question of accepting the facts of one person. If the incident took place in the presence of Mr. Limaye, a Member of this House, and he says so, I would certainly have accepted it

[Shri Y. B. Chavan]

straightway. But Mr. Limaye is accepting the version of some other person. I am neither accepting it nor rejecting it. When Mr. Limaye was there nothing happened in the presence of Mr. Limaye. Naturally he has written this from what he has heard. If he is still prepared to give any further material, I am prepared to examine it.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह विनती है कि आपको नियम 227 में अधिकार है । आप स्वयं कमेटी के सामने इस को भेजिये। उनके जो तथ्य हैं, वे भी आयें और मेरे तथ्य आयें ।

MR. SPEAKER : Let me see. Shri M. R. Krishna.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Sir, on a point of order, under rule 376, regarding the motion which was moved. Has a new procedure been laid down now ?

MR. SPEAKER : I have gone to the next item.

SHRI R. D. BHANDARE : As soon as a notice is given, facts will be hard in this House and the question whether it is a privilege motion or not will be determined in the House by the speaker. Is that the new procedure ?

MR. SPEAKER : I have already gone to the next item. But I may tell the hon. Member that if I want enlightenment on any point, I can certainly ask him to give information. Shri M. R. Krishna.

12.38 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

Naval Ceremonial Conditions of Service and Miscellaneous (Third Amendment) Regulations 1968

THE DEPUTY-MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : I beg to lay on the Table a copy of the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Third Amendment) Regulations 1968, published in Notification No. S.R.O. 5-E in Gazette of India dated the 19th April, 1968, under section 185 of the Navy Act, 1957. [*Placed in library. See* No. LT-1108/68]

12.38½ hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

MR. SPEAKER : I have to inform the House that the Business Advisory Committee met yesterday to consider the feasibility of having discussions regarding (1) the alleged statement by the agriculture Minister of Andhra Pradesh against Harijans; and (2) the discrepancies in the communications received regarding restraint on some Members in Kutch.

As regards the first matter, the Minister of Home Affairs informed the committee that he was expecting a report from the Chief Minister of Andhra Pradesh in the matter by the 6th May. So he would make a statement on or about the 6th May after getting that report. The committee agreed that the question whether a discussion about this matter was necessary and if so, in what form might be considered in the light of the Home Minister's statement after it was made.

As regards the second matter, the Committee decided that there might be one hour discussion on this matter during the next week.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : It has been reported that the Andhra Pradesh Government has stopped its subvention to the UNI because the correspondent of *Patriot* also works for the UNI. Would you please ask him to enquire into that matter also ?

MR. SPEAKER : That is not a part of this thing. Any way if the Home Minister wants, he can certainly look into this thing.